शनिवार , 31 अक्टूबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 66

CITY NEWS MUMBAI

लापरवाही बरतने पर कारोबारी ही नहीं FDA अधिकारी भी नपेंगे! तुकाराम मुंढे ने जारी किए 15 कंप्लायंस ऑर्डर



महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ FDA। तुकाराम मुंढे ने जारी किए कंप्लायंस ऑर्डर। लापरवाही बरतने पर कारोबारियों के साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एफडीए ने कड़े कदम उठाए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा मानकों को सरल बनाने के लिए 15 कंप्लायंस ऑर्डर जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में खाद्य ...शेष 7 पर

पेड़ों की कटाई पर कांग्रेस का महायुति सरकार पर हमला

हर्षवर्धन सपकाल ने उठाए सवाल



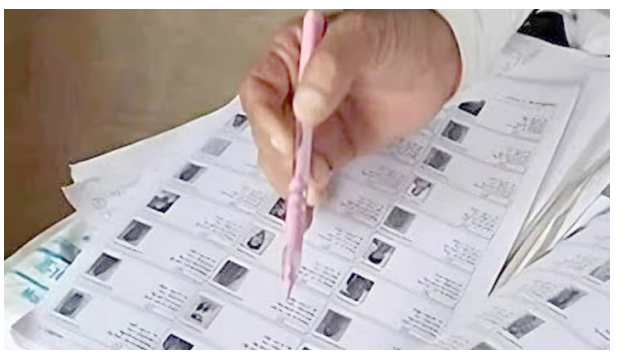
कर्जत के जंगलों में टोरेंट पावर प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल ने महायुति पर निशाना साधा और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की याद दिलाई। हर्षवर्धन सपकाल ने कर्जत-भीमाशंकर जंगलों में पेड़ों की कटाई पर सवाल उठाए। उन्होंने टोरेंट पावर परियोजना को महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ बताया। सपकाल ने सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी का आरोप लगाया। कर्जत-भीमाशंकर के जंगलों में टोरेंट पावर कंपनी की परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने महायुति सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार को परियोजना स्थल का दौरा किया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। मीडिया से बातचीत में सपकाल ने कहा कि सरकार की ओर से इस परियोजना के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार देने और लाखों पेड़ लगाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जंगलों में पेड़ों की ...शेष 7 पर

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में पवार का पावर: शरद पवार गुट का 100% स्ट्राइक रेट, MVA ने जीतीं 3 सीटें



महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर एमवीए ने 3 सीटें जीतकर बढ़त हासिल की। एनसीपी (शरद पवार) ने 100% स्ट्राइक रेट दर्ज किया, वहीं बीजेपी केवल 1 सीट ही जीत पाई। एमवीए ने 5 में से 3 सीटें जीतीं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटें जीतीं, भाजपा को एक मिली। संजय राऊत ने भाजपा पर निशाना साधा। महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के चुनाव परिणाम करीब 45 घंटे की मतगणना के बाद स्पष्ट हो गए हैं। इन चुनावों में महाविकास आघाड़ी ने तीन सीटें जीतकर महायुति के मुकाबले बढ़त हासिल की। एनसीपी (शरद गुट) ने जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ा, उन दोनों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस और शिवसेना (शिंदे गुट) ने एक-एक सीट जीती। भाजपा तीन सीटों पर चुनाव मैदान में थी, लेकिन उसे केवल पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सफलता मिली। इस तरह भाजपा का जीत का स्ट्राइक रेट 33.33 प्रतिशत रहा, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा का स्ट्राइक रेट 100 प्रतिशत रहा। भाजपा को 3 में से 1 सीट भाजपा ने नागपुर स्नातक, पुणे स्नातक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से केवल पुणे शिक्षक सीट पर पार्टी के कौस्तुभ गावडे जीत सके। नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को हराया, जबकि पुणे स्नातक सीट पर भाजपा की स्मिता जाधव को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भाजपा तीन में से केवल एक सीट जीत सकी और उसका स्ट्राइक रेट 33.33 प्रतिशत रहा। शरद पवार की विचारधारा के प्रति समर्थन की पुष्टि : एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के तीन उम्मीदवारों की जीत ने शरद पवार की प्रगतिशील विचारधारा के प्रति समर्थन की पुष्टि की है। शशिकांत ने एक बयान में कहा कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख जाधव और डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटिल ने क्रमशः पुणे और मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से साबित हुआ है कि राकांपा (शप) को आम लोगों और युवाओं का समर्थन अब भी हासिल है। राकांपा (शप) नेता ने उन दावों को खारिज किया कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गई है। शरद पवार ...शेष 7 पर

SIR की समय-सीमा बढ़ी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों को मिली राहत, 13 तारीख तक चलेगा अभियान



चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा बढ़ाई। महाराष्ट्र में अब 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, दिल्ली समेत छह राज्यों में एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाई। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर की गई। महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर को प्रकाशित होगी, जबकि दिल्ली में यह तारीख 22 दिसंबर तय की गई है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य में मतदाताओं को अब दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय ...शेष 7 पर

मिरा-भाईंदर के विकास का मास्टर प्लान तैयार, दिवाली के बाद मंत्री प्रताप सरनाईक करेंगे लंबित कार्यों की समीक्षा

अनधिकृत पानी माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश, दिवाली की छुट्टियों में बच्चों के लिए खुलेगा बाळासाहेब ठाकरे कलादालन

मिरा-भाईंदर, (सिटी न्यूज़ मुंबई)
मिरा-भाईंदर शहर के विकास कार्यों को गति देने और वर्षों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिले के पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ने मिरा-भाईंदर महानगरपालिका के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महानगरपालिका आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री प्रताप सरनाईक ने





विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल बैठकों तक विकास कार्य सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका परिणाम जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने दिवाली के बाद प्रत्येक विभाग से विकास कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें चेना रिवर वॉटरफ्रंट की ओर जाने वाली 18 मीटर चौड़ी सड़क, शिवसृष्टि की ओर जाने वाली 18 मीटर सड़क, खाड़ी किनारे का विकास, महानगरपालिका मुख्यालय की इमारत, उत्तन में सरकारी जमीन पर श्मशानभूमि तथा अन्य श्मशानभूमियों की स्थिति शामिल थी। इसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान के विकास और उनकी प्रतिमा स्थापित करने, ठोस ...शेष 7 पर

मनोज तिवारी ने यमुना के सोनिया विहार घाट पर मारी डुबकी, पराली को लेकर पंजाब की AAP सरकार पर कसा बड़ा तंज

छठ पूजा से पहले यमुना के सोनिया विहार घाट पर मनोज तिवारी ने डुबकी लगाई जिसके बाद सियासी उथल-पुथल मच गई है। पराली को लेकर पंजाब की AAP सरकार पर तंज कसा पंजाब में पराली जलाने के 1,007 मामले दर्ज सौरभ भारद्वाज बोले- BJP के धोखेबाज लोग दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सोनिया विहार घाट पर छठ गीत गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार सुबह यमुना जल में डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने वर्षों तक दिल्ली की सत्ता में रहकर यमुना सफाई के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले किए। आरोप है कि विरोधी दलों ने करोड़ों रुपए का बजट भ्रष्टाचार के नाम चढ़ा दिया। पराली को लेकर पंजाब की AAP सरकार पर तंज कसा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस दौरान पंजाब की AAP सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी प्रदूषण का दोष हरियाणा पर डालती है। जबकि बीजेपी ने डेढ़ साल में आधी नदी साफ कर दी और बाकि बचा काम



आने वाले सालों में हो ही जाएगा। इस दौरान सोनिया विहार घाट पर उन्होंने छठ लोकगीत गाया। छठ मनाने वालों को घाट पर आने का न्योता भी दिया। मनोज तिवारी का दावा है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सफाई कामों से यमुना नदी के प्रदूषण को एक साल में आधा कर दिया। उनका दावा है कि लोग अब यमुना में फिर से छठ पूजा कर पाएंगे। यमुना के कुछ हिस्सों में प्रवासी पक्षियों का आना भी सुधार का संकेत है क्योंकि नदी साफ नहीं होती थी तो ये पक्षी यहां नहीं आते थे। AAP ने भी किया पलटवार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 'X' पर लिखा कि ये बीजेपी के धोखेबाज लोग दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो सभी लोग जानते हैं कि पल्ला से वजीराबाद तक यमुना का 26 किमी. का हिस्सा हमेशा से ही काफी साफ रहा है। DPCC की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो AAP सरकार के समय ये हिस्सा और भी साफ था'। दिल्ली में यमुना नदी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है वैसे-वैसे अधिक प्रदूषित होती जाती है। वजीराबाद और ओखला के बीच का 22 किमी. का हिस्सा अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है, और यही हिस्सा कई नीतिगत प्रयासों का मुख्य केंद्र भी है। आगे भारद्वाज ने कहा कि 'मैं मनोज तिवारी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा को कालिंदी कुंज घाट पर पानी पीने के लिए आमंत्रित करता हूं। पिछले साल भी वे इस चुनौती से भाग गए थे। पंजाब में पराली जलाने के 1,007 मामले दर्ज पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी PPCB के मुताबिक, 29 अक्टूबर तक पंजाब राज्य में पराली जलाने की कुल 1,007 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले तरनतारन से सामने आए हैं।

PM मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा; किसान सम्मान निधि समेत इन चीजों की सौगात



पीएम मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे देशभर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त जारी होगी विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा अहमदाबाद-मेहसाणा सड़क 8 लेन में होगी अपग्रेड 4,030 आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखी जाएगी पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी आज देश भर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से 2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि भारत सरकार का ये बड़ा कदम त्योहार से पहले-पहले लाखों किसानों के चेहरे पर खुशी का कारण बना है। सरकार द्वारा इस बार करीब 18,680 करोड़ से 19,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। बनासकांठा में आयोजित 'किसान उत्सव' के मंच से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे और मौके पर किसानों को संबोधित भी करेंगे।

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस: राबड़ी देवी-तेजस्वी यादव की 19 नवंबर को पेशी, कोर्ट में रहना होगा मौजूद



IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को निर्देश दिए। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में सात अन्य लोगों को बरी भी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेताओं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वे IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पेश हों। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है और स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को हाई कोर्ट से स्टे (रोक) नहीं मिला है, उन्हें अगली सुनवाई में पेश होना होगा। लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव और प्रेम चंद गुप्ता की याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है।

INDIA गठबंधन का जन महाभियोग कार्यक्रम रद्द

INDIA गठबंधन का आज होने वाला 'जन महाभियोग कार्यक्रम' रद्द हो गया। इसमें करीब 20 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और 30 वक्ता शामिल होने थे। INDIA गठबंधन का आज होने वाला 'जन महाभियोग कार्यक्रम' रद्द हो गया। जन महाभियोग कार्यक्रम में करीब 20 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और 30 वक्ता शामिल होने थे। जन महाभियोग कार्यक्रम अब कल दोपहर 2 बजे होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक का 'जन महाभियोग' कार्यक्रम एक दिन के लिए टाल दिया गया है। पहले यह आयोजन आज होना था, लेकिन अब कल दोपहर 3:30 बजे से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होगा। इसमें लगभग 20 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था। इस कार्यक्रम के दौरान 30 वक्ताओं को अपनी बात रखनी थी। मीरा कुमार को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी, और मल्लिकार्जुन खरगे को प्रस्ताव पेश करना था। इस कार्यक्रम के समापन के लिए राहुल गांधी का नाम चर्चा में था। बारिश के कारण रद्द हुआ कार्यक्रम सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में भारी बारिश के कारण यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है, जिसकी वजह से अब मल्लिकार्जुन खरगे के आवास के बाहर जरूरी तैयारियां नहीं हो सकीं। जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।

25 वर्षे विकासाची 25 मिरा भाईंदर महानगरपालिका "माझे शहर, माझा अभिमान"

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईंदर (प.), ता.ठाणे-401101 दुरध्वनी क्रं.28192828
बांधकाम / विद्युत विभाग

पुण्यश्लोक 300

जा.नं. मनपा/साबां/वि/ ५३४६/२०२६-२७ **दि.३०/१०/२०२६**

// जाहिर नोटीस //

मिरा भाईंदर शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील मिरारोड (पुर्व) शांतीनगर शितलनगर शांती पार्क परिसरातील शहीद भगतसिंग उद्यान, शांती प्लाझा, मिर्ची ब्युटीक समोरील रस्ता हा १२.०० मीटर रुंदीचा दर्शविण्यात आला आहे. मिरारोड (पुर्व) भागातुन शितलनगर, शांतीनगर, शांती पार्क या भागाकडे व पुढे सृष्टी, पेणकरपाडा, मिरागांव व राष्ट्रीय महामार्गास जोडणारा सदर रस्ता असून सदर रस्त्यावरुन मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक व रहदारीची वर्दळ असते. सदर रस्त्याचे १८.०० मीटर पर्यंत रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २१० अन्वये मा.आयुक्त यांना मा.स्थायी समितीच्या पुर्व मान्यतेने कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याचा एका किंवा दोन्ही बाजुच्या रेषा विहीत करण्याचा अधिकार आहे. सदर तरतुदीनुसार वर प्रस्तावित रस्त्याची रुंदी १८.०० मीटर ठेवण्यासाठी रस्त्याच्या रेषा विहीत करावयाच्या आहेत.

सदर प्रस्तावाबाबत हरकती व सुचना असल्यास लेखा म्हणणे कार्यकारी अभियंता (साबां/वि.) विभाग, चौथा मजला, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, ता.जि.ठाणे – ४०११०१ यांचे कार्यालयात दि.०२ डिसेंबर, २०२६ रोजी पर्यंत सादर करण्यात यावे.

सदर रस्त्याचा नकाशा व अधिक माहिती कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व वेळेत पहावयास मिळेल. मुदतीत आलेल्या हरकती व सुचना यांचा विचार केला जाणार नाही.

जा. क्र. मनपा/मावाज/ E-१००९२०४०/२०२६-२७
दि. ३०/१०/२०२६
ठिकाण :- भाईंदर
दि.३० ऑक्टोंबर, २०२६

सही/-
(दिपक खांबित)
शहर अभियंता
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

"माझे शहर, माझा अभिमान"

नीतीश होते तो ये नौबत नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह का बड़ा बयान, बोले- जमानत मिल जाएगी

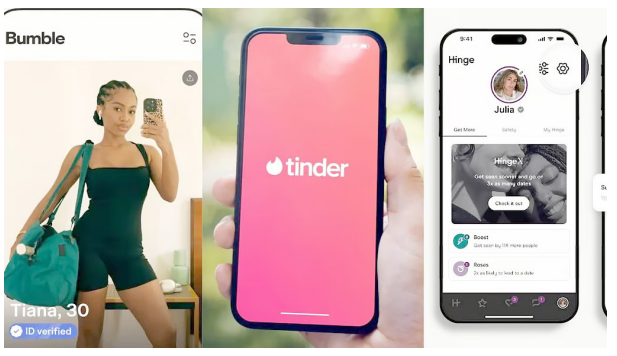
अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के बीमार पड़ने के बाद पार्टी में बदलाव का दावा किया। दुलार चंद यादव हत्याकांड में 1 दिसंबर तक सरेंडर करने की बात कही। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के बीमार पड़ने के बाद पार्टी में बदलाव का दावा किया। दुलार चंद यादव हत्याकांड में 1 दिसंबर तक सरेंडर करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। जनता दल (यूनाइटेड) जेडी(यू) से निकाले गए बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह निर्देश उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जो दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी हैं, उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मृतक के पोते नीरज कुमार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस हत्या के मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने कहा, "मुझे पूरा यकीन था कि अगर नीतीश कुमार पहले की तरह अपने पद पर बने रहते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है, वह



उनके बीमार पड़ने के बाद ही हुआ है। पार्टी ने उन्हें हटा दिया है। अब पार्टी खुद तय करे कि वह कैसे काम करना चाहती है। पार्टी के लिए कहीं भी जीतना मुश्किल हो जाएगा।" दुलार चंद हत्याकांड पर अनंत सिंह का बड़ा बयान दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 दिसंबर तक सरेंडर करने के निर्देश पर, पार्टी से निकाले गए JDU विधायक अनंत सिंह बोले, "मैं कोर्ट के सामने सरेंडर कर दूंगा। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, और कोर्ट जो भी फैसला लेगा, वह हमें मंजूर होगा। कोर्ट मुझे फिर से जमानत दे देगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे पहले भी भरोसा था और आज भी है।" अनंत सिंह ने नीरज कुमार को दोषी ठहराते हुए कहा, "नीरज कुमार ने मुझे दुलार चंद हत्याकांड में फंसाया था, जबकि यह घटना हमसे तीन किलोमीटर दूर हुई थी। बाद में, जब मेरी जमानत की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, तो नीरज इस मामले को दिल्ली ले गए। मुझे कुछ महीनों बाद इस बारे में पता चला। जब मुझे इस रिपोर्ट का पता चला, तो मैंने चुनावों के दौरान खुलकर उनका विरोध किया। इसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, इन सबके पीछे सिर्फ नीरज कुमार थे।" दुलारचंद यादव हत्याकांड मामला क्या है? गौरतलब है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, 30 अक्टूबर को पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित बसावनचक गांव में जन सुराज पार्टी के एक उम्मीदवार के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। खबरों के अनुसार, मोकामा से तत्कालीन जेडी(यू) उम्मीदवार अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसी झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की जान चली गई।

डेटिंग ऐप Tinder- Bumble और Hinge पर 75% प्रोफाइल फर्जी; जानें कैसे बचें रोमांस स्कैम से?

क्या आप भी डेटिंग ऐप चलाते हैं? यदि हां तो ये खबर आपके लिए है। डेटिंग ऐप पर प्यार और रोमांस के नाम पर कैसे स्कैम होता है? और कैसे आप अपने आप को इस स्कैम से बचा सकते हैं? डेटिंग ऐप में कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है। डेटिंग ऐप को लेकर सर्वे में क्या रिजल्ट आया है। डेटिंग ऐप ने स्कैम से बचने के लिए क्या बदलाव किए हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए जीवनसाथी या पार्टनर तलाशना अब आम हो गया है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर प्यार के नाम पर ठगी का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। साइबर अपराधी फर्जी प्रोफाइल, चोरी की तस्वीरों और झूठी पहचान के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले दोस्ती और प्यार का भरोसा जीतते हैं, फिर निवेश, बीमारी या किसी आपात स्थिति का बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं। इसी



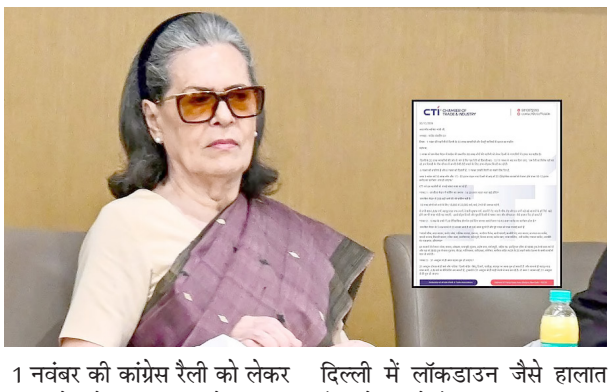
खतरे को देखते हुए डेटिंग ऐप Tinder और Hinge की पैरेंट कंपनी मैच ग्रुप ने भारत में साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है। 21 अक्टूबर को मैच ग्रुप ने गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझेदारी की। इस अभियान में मैच ग्रुप का एक अन्य डेटिंग प्लेटफॉर्म द लीग भी शामिल है। इसका मकसद लोगों को रोमांस स्कैम के संकेत पहचानने, संभावित पार्टनर की पहचान जांचने और साइबर अपराध की शिकायत के लिए आधिकारिक माध्यमों की जानकारी देना है। यह पहल ऐसे समय में आई है, जब डेटिंग ऐप पर फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कंपनियां सुरक्षा के लिए नए फीचर ला रही हैं, लेकिन चुनौती यह है कि साइबर ठग लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। डेटिंग ऐप पर कैसे काम करता है रोमांस स्कैम? रोमांस स्कैम में ठग शुरुआत में सीधे पैसे नहीं मांगते। वे पहले किसी की तस्वीर चुराकर आकर्षक प्रोफाइल बनाते हैं और खुद को भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं। इसके बाद कई हफ्तों या महीनों तक बातचीत करके सामने वाले का विश्वास जीतते हैं। जब भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो जाता है, तब ठगी का खेल शुरू होता है। कोई व्यक्ति अचानक मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर पैसे मांग सकता है, तो कोई विदेश यात्रा या वीजा फीस के नाम पर आर्थिक मदद मांगता है। ठगी का एक तरीका यह भी है कि अपराधी डेटिंग ऐप से बातचीत को व्हाट्सऐप या दूसरे निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। इसके बाद वे क्रिप्टोकरेंसी या शेयर बाजार में निवेश की सलाह देते हैं और कम समय में मोटा मुनाफा दिलाने का दावा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को दिया बड़ा झटका, सरेंडर कर जेल लौटने को कहा, 1 दिसंबर तक का दिया समय



दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने और जेल लौटने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने जमानत को चुनौती दी थी बिहार सरकार ने अनंत सिंह के खिलाफ 62 मुकदमों की जानकारी दी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण कर जेल जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुनाया है। दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने आज इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान अनंत सिंह के वकील ने बताया कि उनके परिवार में 25 नवंबर को एक शादी है। इस पर कोर्ट ने मोकामा विधायक को शादी के बाद 1 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर जेल लौटने का आदेश दिया।

राहुल से टूटी उम्मीद, अब सोनिया गांधी को CTI ने लिखा पत्र, रामलीला मैदान या बुराड़ी? कांग्रेस को दिए 2 विकल्प



1 नवंबर की कांग्रेस रैली को लेकर CTI ने सोनिया गांधी से तारीख बदलने की मांग की है। संगठन ने दिल्ली के बाजारों में कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस के सामने दो मांगें रखी हैं। रामलीला मैदान के 5 किमी के दायरे में 20 बड़े थोक और खुदरा बाजार स्थित हैं। सेंट्रल दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि INDIA गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को दिवाली के बाद, यानी 10-11 नवंबर के बाद की किसी तारीख पर पुनर्निर्धारित किया जाए।

शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का निधन, भोपाल AIIMS में ली अंतिम सांस; जैत में होगा अंतिम संस्कार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की माता काशीबाई का निधन, भोपाल AIIMS में ली अंतिम सांस। पार्थिव शरीर जैत ले जाया जाएगा, दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का भोपाल एम्स में निधन। भोपाल के साकेत नगर स्थित आवास पर सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। सीहोर जिले के पैतृक गांव जैत में दोपहर 3 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का शुक्रवार सुबह निधन हो गया, वह पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थीं और उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह उन्होंने भोपाल स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिवार और शुभचिंतकों में शोक का माहौल है। काशीबाई का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जैत





में किया जाएगा। परिवार की ओर से अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए यह व्यक्तिगत क्षति है। भोपाल स्थित आवास पर होंगे अंतिम दर्शन मिली जानकारी के मुताबिक, काशीबाई का पार्थिव शरीर भोपाल के साकेत नगर स्थित शिवराज सिंह चौहान के निवास पर रखा गया है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को सीहोर जिले के जैत गांव ले जाया जाएगा। यहां दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के गांव पहुंचने की संभावना है। अंतिम संस्कार में शामिल होकर लोग काशीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शिवराज सिंह के बचपन में हुआ था मां का निधन शिवराज सिंह चौहान के पारिवारिक जीवन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, उनके पिता प्रेम सिंह चौहान की पहली शादी सुंदरबाई चौहान से हुई थी। सुंदरबाई के तीन बेटे और एक बेटी हुई। इनमें शिवराज सिंह चौहान, रोहित सिंह, नरेंद्र सिंह और बेटी शशि सिंह शामिल हैं। हालांकि, शिवराज सिंह चौहान के बचपन में ही उनकी मां सुंदरबाई का निधन हो गया था। इसके बाद उनके पिता प्रेम सिंह चौहान ने दूसरी शादी काशीबाई से की थी। काशीबाई के परिवार में हैं एक बेटा प्रेम सिंह चौहान से शादी के बाद काशीबाई के एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम वरुण सिंह है। इस तरह काशीबाई शिवराज सिंह चौहान के परिवार का हिस्सा बनीं और परिवार के साथ उनका जुड़ाव रहा। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया था।

सम्पादकीय

पेड़ों को काटना विकास नहीं, बल्कि विनाश है!

कर्जत-भीमाशंकर के साई डोंगर क्षेत्र में एक विद्युत परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई जारी है, जो विकास नहीं बल्कि विनाश है! हम इस विनाश का कड़ा विरोध करते हैं! महाराष्ट्र को विकास की आवश्यकता है; लेकिन यह प्रकृति का बलिदान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। महाराष्ट्र में विकास की सही परिभाषा क्या है? क्या हम हजारों पेड़ों को काटकर, जैव विविधता को नष्ट करके और आने वाली पीढ़ियों की आजीविका को कमजोर करके इसे विकास कह सकते हैं? मुंबई के पास कर्जत-भीमाशंकर क्षेत्र में टॉरेंट कंपनी की प्रस्तावित बिजली परियोजना के लिए 33,000 पेड़ों की कटाई एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस परियोजना की पर्यावरणीय लागत कौन वहन करेगा और इससे किसे लाभ होगा। महाराष्ट्र के लिए ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है। हालांकि, सरकार का यह मानना कि विकास के लिए पर्यावरण विनाश अपरिहार्य है, गलत है। उद्योग की जरूरतों और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए, कर्जत-भीमाशंकर में वृक्षों की कटाई का मुद्दा केवल एक परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश आवश्यक है? यही मूल प्रश्न है। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित कर्जत-भीमाशंकर क्षेत्र वन संसाधनों, जल संसाधनों और जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पेड़ बारिश के पानी को जमीन में रिसने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है, तापमान नियंत्रित रहता है और अनगिनत वन्यजीवों को आवास मिलता है। अगर हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं, तो इसके परिणाम केवल परियोजना की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे; इसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या इस परियोजना के लिए 33,000 पेड़ काटने की अनुमति देते समय पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किया गया था? यह अस्वीकार्य है कि स्थानीय नागरिकों और प्रकृति को एक औद्योगिक परियोजना की कीमत चुकानी पड़े। यह सवाल उठाना कि विकास से किसे लाभ होगा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का बोझ कौन उठाएगा, विकास-विरोधी मुद्दा नहीं है; यह पर्यावरणीय न्याय का मुद्दा है। आरे वन और विकास के दावों के बीच विरोधाभास मुंबई के लिए, आरे वन हरियाली, जैव विविधता और वन्यजीवों के आवास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जब मेट्रो परियोजना के लिए आरे में पेड़ काटने का निर्णय लिया गया, तो पर्यावरणविदों, स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। पेड़ काटने के तरीके ने भी सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर ध्यान दिया था। किसी परियोजना को विकास का नाम देने से उसके पर्यावरणीय प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। परियोजनाओं का वायु, जल, वनों और स्थानीय जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव परियोजनाओं, उद्घाटनों और विज्ञापनों की संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इन्फ्रामैन या डिजास्टरमैन? देवेंद्र फडणवीस सरकार बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दे रही है। हालांकि, राजमार्गों, मेट्रो, बिजली परियोजनाओं और सीमेंट-कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण करना व्यापक विकास नहीं है। विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकना या कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ बनने की होड़ में देवेंद्र फडणवीस पर्यावरण के मामले में 'विनाशकारी' बनते जा रहे हैं, यही कारण है कि उनकी सरकार के पर्यावरण संबंधी फैसलों की आलोचना हो रही है। विकास के विज्ञापनों से नष्ट हुए वृक्षों की संपदा को बहाल नहीं किया जा सकता और प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र को रातोंरात ठीक नहीं किया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वालों को विकास विरोधी कहना उचित नहीं है। 33 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा का क्या हुआ? फडणवीस सरकार के कार्यकाल में 33 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च किए गए। लेकिन सरकार यह जानकारी नहीं देती कि लगाए गए पौधों में से कितने जीवित रहे, वे कहाँ हैं और उनकी देखभाल कैसे की गई। सरकार को वृक्षारोपण के आंकड़े, पौधों की उत्तरजीविता दर, इस पर खर्च की गई लागत और उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। क्योंकि परिपक्व पेड़ों के स्थान पर कुछ पौधे लगाने से पर्यावरण को तुरंत लाभ नहीं मिलता। बड़े पेड़ों की छाया, कार्बन अवशोषण क्षमता, मृदा संरक्षण और जैव विविधता को सहारा देने की क्षमता विकसित होने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए, सरकार को वृक्षारोपण से बचने, यदि अपरिहार्य हो तो इसकी दर कम करने और वैज्ञानिक तरीके से नुकसान की भरपाई और पुनर्स्थापन करने का आदेश अपनाना चाहिए। वृक्षारोपण के नारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वास्तविक वनों का संरक्षण है। सूखे के दौरान वनों की कटाई का तेरहवाँ महीना महाराष्ट्र जल संकट, अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में वनों की रक्षा और जल संसाधनों का संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन, प्राकृतिक जल प्रवाह में परिवर्तन और स्थानीय तापमान वृद्धि जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं। प्रकृति को नष्ट करके किया गया विकास अस्थायी लाभ तो प्रदान कर सकता है; लेकिन इसका पर्यावरणीय बोझ आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। इसलिए, प्रत्येक बड़ी परियोजना पर निर्णय लेते समय इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। हमें पर्यावरण के अनुकूल विकास की आवश्यकता है, न कि उद्योगपतियों के अनुकूल विकास की! महागठबंधन सरकार के विकास मॉडल में उद्योग और बुनियादी ढांचे के विस्तार के आगे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और स्थानीय नागरिकों के हितों को गौण स्थान दिया गया है।

लेखक गाँव: हिमालय में साहित्य, संस्कृति और वैश्विक संवाद का संगम

— डॉ. सत्यवान सौरभ
— डॉ. प्रियंका सौरभ

हिमालय केवल पर्वतों की शृंखला नहीं है; वह भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, प्राकृतिक संपदा और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत प्रतीक है। इसकी ऊँची चोटियाँ मनुष्य को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती हैं, जबकि इसकी नदियाँ जीवन, निरंतरता और सभ्यताओं के विकास का संदेश देती हैं। इसी हिमालयी चेतना को साहित्य, कला, संस्कृति और वैश्विक संवाद से जोड़ने वाला तृतीय अंतरराष्ट्रीय 'स्पर्श पर हिमालय' 2026 महोत्सव उत्तराखंड के देहरादून स्थित लेखक गाँव, थानो में सहभागिता का यादगार अवसर बना। इस आयोजन में विभिन्न देशों तथा भारत के अनेक राज्यों से आए साहित्यकारों, कलाकारों, विद्वानों और सृजनशील व्यक्तियों ने भाग लिया। आज जब विश्व राजनीतिक तनाव, युद्ध, सांस्कृतिक टकराव, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विभाजन जैसी चुनौतियों से घिरा है, तब साहित्य और संस्कृति की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति अक्सर देशों और समाजों के बीच सीमाएँ खींचती है, परंतु साहित्य मनुष्यों को उनकी साझा संवेदनाओं के आधार पर जोड़ता है। भाषाएँ भिन्न हो सकती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं और जीवनशैली में अंतर हो सकता है, किंतु प्रेम, करुणा, शांति, न्याय और मानवीय गरिमा की आकांक्षाएँ सर्वत्र समान हैं। साहित्य इन्हीं साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है। लेखक गाँव की अवधारणा 'स्पर्श पर हिमालय' जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन इस विचार को व्यवहार में उतारने का अवसर प्रदान करते हैं। जब विभिन्न देशों और भारतीय राज्यों से आए रचनाकार एक मंच पर एकत्र होते हैं, तो विचारों का आदान-प्रदान केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहता। यह विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक अनुभवों, साहित्यिक प्रवृत्तियों और समकालीन चुनौतियों को समझने का माध्यम बनता है। ऐसे मंच सिद्ध करते हैं कि साहित्य और संस्कृति आज भी मानव को साझा मानवीयता के सूत्र में बाँधने की क्षमता रखते हैं। इस आयोजन का स्थल लेखक गाँव अपने आप में विशेष महत्त्व रखता है। ग्रामीण परिवेश में साहित्यिक गतिविधियों का विस्तार इस धारणा को चुनौती देता है कि रचनात्मकता और बौद्धिक विमर्श केवल महानगरों, विश्वविद्यालयों या बड़े सभागारों तक सीमित हैं। गाँव भारतीय समाज की स्मृतियों, लोकभाषाओं, लोककलाओं, परंपराओं और जीवनानुभवों के प्रमुख स्रोत रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में स्थापित साहित्यिक मंच लेखकों को अपनी जड़ों से जुड़ने और स्थानीय अनुभवों को वैश्विक संदर्भों में प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। सृजन का हिमालयी केंद्र लेखक गाँव केवल कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान नहीं है; यह लेखन, चिंतन, अनुसंधान, अनुवाद, कला और सांस्कृतिक संवाद का जीवंत केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ प्रकृति के समीप रहकर लेखक अपनी रचनात्मक ऊर्जा को नई दिशा दे सकते हैं। हिमालय की शांति, विविधता और गहराई रचनाकारों को समाज, संस्कृति और मानवीय जीवन के नए प्रश्नों से जोड़ती है। यही कारण है कि लेखक गाँव को एक ऐसे सांस्कृतिक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पारंपरिक ज्ञान और समकालीन चिंतन का संगम संभव होता है। भारतीय साहित्य की शक्ति उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में निहित है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊँनी और अन्य भाषाएँ अपने-अपने समाजों की स्मृतियों, संघर्षों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती हैं। लेखक गाँव जैसे मंच इन भाषाओं के बीच संवाद बढ़ाने, क्षेत्रीय साहित्य के अनुवाद को प्रोत्साहित करने और विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों को एक-दूसरे की रचनात्मक दुनिया से परिचित कराने के अवसर प्रदान करते हैं। साहित्य की सामाजिक भूमिका साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को संवेदनशील बनाना और समय के प्रश्नों से उसका सामना कराना भी है। आज साहित्यकारों के सामने बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, जातिगत विषमता, उपभोक्तावाद, डिजिटल माध्यमों के दुष्प्रभाव और पर्यावरणीय संकट जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। रचनाकार अपनी लेखनी के माध्यम से इन विषयों पर जनचेतना विकसित कर सकते हैं। साहित्य जब समाज के वंचित वर्गों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं की आवाज बनता है, तब वह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सार्थक योगदान देता है। इस संदर्भ में लेखक गाँव जैसे आयोजन स्थलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसे केंद्र केवल मंचीय प्रस्तुतियों, सम्मान समारोहों और औपचारिक वक्तव्यों तक सीमित न रहें, बल्कि इनके परिणाम पुस्तकों के प्रकाशन, अनुवाद परियोजनाओं, शोध संवादों, युवा लेखकों के प्रशिक्षण और विभिन्न भाषाओं के बीच दीर्घकालीन सहयोग के रूप में भी सामने आने चाहिए। यदि यहाँ बने संपर्क आगे साहित्यिक गतिविधियों, अनुवाद और रचनात्मक सहयोग में परिवर्तित होते हैं, तो लेखक गाँव की उपयोगिता और व्यापक हो सकती है। हिमालय और पर्यावरण की चेतना हिमालय का पर्यावरणीय महत्त्व भी लेखक गाँव के विमर्श का स्वाभाविक विषय है। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित निर्माण, वनों का क्षरण, भूस्खलन, जलस्रोतों का सूखना और अनियोजित पर्यटन पर्वतीय क्षेत्रों के सामने गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। अतः हिमालय के प्रति संवेदनशीलता केवल भावनात्मक विषय नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रश्न भी है। साहित्य प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को नए सिरे से समझने तथा विकास की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। डिजिटल युग ने साहित्यिक संवाद की संभावनाओं को और विस्तृत किया है। अब लेखक गाँव में आयोजित चर्चाएँ, व्याख्यान और रचनात्मक प्रस्तुतियाँ डिजिटल माध्यमों से दूर-दराज के पाठकों तक पहुँच सकती हैं। इससे उन लेखकों और पाठकों को भी भागीदारी का अवसर मिल सकता है, जो आर्थिक, भौगोलिक या अन्य कारणों से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। इसके लिए डिजिटल सामग्री का व्यवस्थित संकलन, विश्वसनीय अभिलेखीकरण और बहुभाषी उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे आयोजनों की वास्तविक सफलता प्रतिभागियों की संख्या से आगे बढ़कर उनके बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव से निर्धारित होती है। यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि लेखक गाँव नई रचनात्मक साझेदारियों को कितना प्रोत्साहित करता है, युवा पीढ़ी में साहित्य के प्रति कितनी रुचि जगाता है और समाज के विविध वर्गों की आवाज को कितना स्थान देता है। साहित्यिक मंच तभी अधिक प्रभावशाली बनते हैं, जब वे संवाद के साथ-साथ विचारों की विविधता, रचनात्मक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक दृष्टि का भी सम्मान करते हैं। देहरादून के लेखक गाँव, थानो में आयोजित तृतीय अंतरराष्ट्रीय 'स्पर्श पर हिमालय' 2026 में सहभागिता ने साहित्य और संस्कृति की इसी व्यापक भूमिका पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। ऐसे मंच हमें याद दिलाते हैं कि साहित्य की सीमाएँ राजनीतिक भूगोल से बड़ी होती हैं और संस्कृति का वास्तविक वैभव विविधताओं के सम्मान में निहित है। हिमालय का स्पर्श तभी सार्थक होगा, जब उसकी प्रेरणा हमारे विचारों में उदारता, हमारी रचनाओं में संवेदना और हमारे व्यवहार में मानवीय एकता के रूप में दिखाई दे। यही लेखक गाँव की सबसे बड़ी उपलब्धि और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। (डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

- डॉ० सत्यवान सौरभ,
कवि, सामाजिक विचारक एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी,
हरियाणा – 127045, मोबाइल :9466526148,01255281381

सही इतिहास लेखन की जरूरी पहल

हाल में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी एंड बियांड, भाग-2' जारी की। यह इतिहास के पुनर्पाठ और पुनर्लेखन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह दिल्ली-केंद्रित इतिहास से बाहर निकलकर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं, उपेक्षित राजवंशों और सांस्कृतिक प्रतिरोध की गाथाओं को स्थान देती है। कथित 'गंगा-जमुनी तहजीब' के नाम पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में दिल्ली सल्तनत के गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों तथा मुगलों को अधिक स्थान मिलता रहा, जबकि अहोम, मेवाड़, मराठा और विजयनगर जैसे साम्राज्यों को क्षेत्रीय इतिहास कहकर सीमित कर दिया गया। जिस अहोम साम्राज्य ने छह शताब्दियों तक स्वतंत्रता बनाए रखी, जिस मेवाड़ ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, जिस मराठा शक्ति ने मुगल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई और जिस विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कला, साहित्य और स्थापत्य को समृद्ध किया, उन्हें इतिहास में अपेक्षित स्थान क्यों नहीं मिला? चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और काकतीय राजवंशों की उपेक्षा क्यों हुई? भारत का इतिहास केवल विदेशी आक्रमणों और पराजयों का वृत्तांत नहीं है। यह हजार वर्षों तक चले संघर्ष, प्रतिरोध, बलिदान और सांस्कृतिक स्वाभिमान की गाथा भी है। जिस इस्लामी आक्रमण की आंधी ने पश्चिम एशिया की प्राचीन सभ्यताओं के राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बदल दिया, उसके सामने भारत ने अपनी सभ्यतागत निरंतरता कैसे बनाए रखी? इसके पीछे हमारी सामरिक शक्ति, सामाजिक संरचना, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक प्रतिरोध की कौन-सी धाराएं सक्रिय थीं? इन प्रश्नों का उत्तर तलाशना इतिहास लेखन का अनिवार्य दायित्व है। अपने गौरव, संघर्ष और स्वाभिमान को इतिहास में स्थान देना आखिर अनुचित कैसे हो सकता है? नई पुस्तक में महाराणा प्रताप, दिवेर का युद्ध, सरायघाट में लचित बरफुकन के नेतृत्व में मुगलों की पराजय, मराठों के स्वराज और सिख गुरुओं के बलिदान इसी दृष्टि को पुष्ट करते हैं।

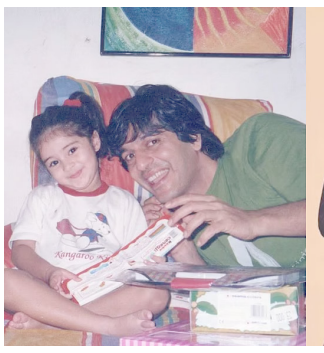
प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई 'मिर्जापुरः द मूवी', कालीन भैया और गुड्डू पंडित के भौकाल के लिए हो जाइए तैयार



मिर्जापुरः द मूवी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु की फिल्म में सत्ता की जंग, दुश्मनी और पुराने किरदारों का भौकाल देखने को मिलेगा। 'मिर्जापुरः द मूवी' का एक्सक्लूसिव ग्लोबल प्रीमियर प्राइम वीडियो पर हो गया है। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी सीजन 1 के दौर में लौटती है, जहां सत्ता और दुश्मनी की जंग देखने को मिलेगी। ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली 'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी एक बार फिर दर्शकों के बीच लौट आई है। इस बार कहानी वेब सीरीज से आगे बढ़कर फिल्म के रूप में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। 'मिर्जापुरः द मूवी' का एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर प्राइम वीडियो पर हो गया है। फिल्म भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम हो रही है। ऐसे में फैंस एक बार फिर पूर्वांचल की सत्ता, दुश्मनी और गैंगवार की दुनिया में पहुंचने वाले हैं। 'मिर्जापुरः द मूवी' में अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, श्वेता त्रिपाठी शर्मा और सोनल चौहान समेत कई कलाकार अहम किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म में पुराने चेहरों के साथ कहानी को नए अंदाज में पेश किया गया है, जिससे फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है। सीजन 1 के दौर में पहुंचेगी फिल्म की कहानी 'मिर्जापुरः द मूवी' की कहानी दर्शकों को 'मिर्जापुर' के पहले सीजन के दौर में लेकर जाती है। इसमें एक बार फिर सत्ता की लड़ाई, दुश्मनी और गद्दी हासिल करने की जंग देखने को मिलेगी। इस बार कहानी का दायरा पूर्वांचल से लेकर रेगिस्तान तक फैला हुआ है। फिल्म में दर्शकों को कई पुराने और लोकप्रिय किरदारों के साथ मिर्जापुर की दुनिया का एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। एक्सटेंडेड कट में दिखेंगे अनदेखे सीन 'मिर्जापुरः द मूवी' का एक्सटेंडेड कट भी दर्शकों के लिए खास है। इसके जरिए फैंस को कुछ ऐसे सीन देखने को मिलेंगे, जो पहले सामने नहीं आए थे।

इससे कहानी और किरदारों को करीब से समझने का मौका मिलेगा। फिल्म को पुनीत कृष्णा ने लिखा है और गुरमीत सिंह ने इसका निर्देशन किया है। वहीं, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म एक बार फिर मिर्जापुर के भौकाल को दर्शकों के सामने लेकर आई है।

अनन्य पांडे के बर्थडे पर मां भावना ने शेयर किया क्यूट वीडियो, पापा चंकी के साथ दिखी अनन्या की मस्ती





अनन्या पांडे के जन्मदिन पर मां भावना पांडे ने उनका बचपन का प्यारा वीडियो साझा किया। क्लिप में चंकी पांडे और अनन्या के बीच पिता-बेटी की खास बॉन्डिंग देखने को मिली। 28 साल की हुईं अनन्या पांडे, मां ने शेयर किया बचपन का वीडियो पापा चंकी पांडे के साथ दिखी अनन्या की क्यूट बॉन्डिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से शुरू किया था फिल्मी सफर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आज 28 साल की हो गई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे 90 के दशक के हीरो चंकी पांडे की बेटी है। अनन्या के जन्मदिन के मौके पर चंकी पांडे की पत्नी और अनन्या की मां भावना पांडे ने अपनी बेटी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक क्यूट वीडियो शेयर कर अनन्या के बचपन की यादें ताजा कर दी है। अनन्या पांडे की बचपन की वीडियो की पोस्ट अनन्या पांडे की मां भावना पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी को बर्थडे विश करते हुए एक स्पेशल वीडियो पोस्ट की है।

महिलाओं की गैंगस्टर दुनिया, सत्ता की जंग और बदले की कहानी, जानें क्यों देखें 'अक्का' सीरीज

कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की क्राइम थ्रिलर सीरीज अक्का महिलाओं के वर्चस्व वाले काल्पनिक शहर की कहानी है। दमदार अभिनय और एक्शन से सजी यह सीरीज कई दिलचस्प मोड़ पेश करती है। नेटफ्लिक्स की अक्का में महिलाओं की सत्ता की कहानी कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की दमदार एक्टिंग महिला गैंगस्टर सिंडिकेट और बदले की दिलचस्प कहानी नेटफ्लिक्स पर हाल ही में महिला सशक्तीकरण से जुड़ी एक बेहतरीन वेब सीरीज रिलीज हुई है। क्राइम थ्रिलर सीरीज अक्का की कहानी महिलाओं के वर्चस्व और उनकी सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आती है। यशराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट के द्वारा प्रोड्यूस इस वेब सीरीज का डायरेक्शन धर्मराज शेट्टी ने किया है। इस वेबसीरीज की कहानी 1980 के दशक के काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर पेरुनुरु की पृष्ठभूमि पर बनी यह कहानी महिलाओं के एक शक्तिशाली गैंगस्टर सिंडिकेट, उनकी परंपराओं और सत्ता की लड़ाई पर आधारित है। इस सीरीज में कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाली हैं। कैसी है वेब सीरीज अक्का? नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज महिला गैंगस्टर सिंडिकेट, पारिवारिक विरासत, सत्ता संघर्ष और बदले की कहानी को एक साथ पेश करती है। कीर्ति सुरेश और राधिका





आप्टे की दमदार एक्टिंग दर्शकों का दिल जीत लेगी। अक्का में शानदार प्रोडक्शन डिजाइन और प्रभावशाली एक्शन इसे बाकी वेब सीरीज से काफी अलग दिखाता है। समय के अलग-अलग हिस्सों में घूमती कहानी ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़कर रखती है। अगर आप ऐसी क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते है जिसमें महिलाओं महिलाओं के वर्चस्व वाली एक अलग दुनिया और दमदार महिला किरदारों हो, तो ये वेब सीरीज आपको काफी पसंद आ सकती है। कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की दमदार एक्टिंग अक्का वेब सीरीज में राधिका आप्टे की दमदार एक्टिंग इसे और भी खास बनाती है। रुद्रा के किरदार में राधिका आप्टे बदले की भावना और महत्वाकांक्षा से भरी रुद्र पेरुनुरु की सत्ता को चुनौती देने आती है। उसके किरदार में कई लेयर हैं, जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर भवानी का किरदार निभाने वाली कीर्ति सुरेश कमजोरी, गुस्से और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाती हुई नजर आती है। वह अपने परिवार की विरासत और इलाके के बिजनेस पर बने कंट्रोल को अपने हाथों में रखकर बचाने की कोशिश करती है। इस वेब सीरीज में भवानी के किरदार को परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की मौत और बदलते हालात के बीच उन्हें कई कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे रुद्रा के अतीत से जुड़े राज भी ऑडियंस के सामने आने लगते हैं। को एक्टर्स का बेमिसाल योगदान इस वेब सीरीज में तन्वी आजमी के अलावा अंशुमान पुष्कर और महेश मांजरेकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। पुरुष किरदार कहानी का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन पेरुनुरु की सत्ता और फैसलों पर महिलाओं का ही नियंत्रण है। महेश मांजरेकर का किरदार कहानी के पहले हिस्से के अंतिम पड़ाव में एक अहम खुलासा करता है।

मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव, रॉबिन उथप्पा समेत इन दिग्गजों की हुई एंट्री

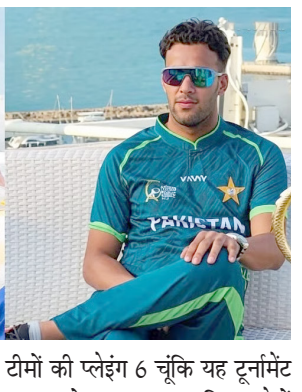




IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने रॉबिन उथप्पा को नया बैटिंग कोच और मिशेल मैक्लेनाघन को बॉलिंग कोच बनाया गया है, जबकि कीरोन पोलार्ड मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। मुंबई इंडियंस ने रॉबिन उथप्पा को नया बैटिंग कोच बनाया है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने मिशेल मैक्लेनाघन को बॉलिंग कोच बनाया है। वहीं कीरोन पोलार्ड मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। मुंबई इंडियंस (MI) आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के 20 वें सीजन के लिए बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाली है।

पाकिस्तान ने भारत को एकतरफा मुकाबले में हराया, 4 ओवर में चेज 88 रन का टारगेट





हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने 89 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे पाकिस्तान ने 23 गेंदों में ही चेज कर डाला। हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में अब्बास अफरीदी की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय टीम को हरा दिया है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया ने 89 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे पाकिस्तान ने 23 गेंदों में ही चेज कर डाला। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। इससे पहले पाकिस्तान को यूएई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने शशांक सिंह की तूफानी पारी के दम पर 88 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस मामूली से स्कोर को पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 23 गेंदों में ही चेज कर डाला। क्रुणाल पांड्या को पहले ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के पड़े। IND vs PAK: ऐसी रही दोनों टीमों की प्लेइंग 6 चूंकि यह टूर्नामेंट 6-6 ओवर रहा। इसलिए दोनों टीमों ने अपनी बेस्ट 'प्लेइंग 6' मैदान पर उतारी । भारत प्लेइंग-6: नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, राहुल तेवतिया (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या (कप्तान), शशांक सिंह, कुलवंत खेजरोलिया, टी नटराजन। पाकिस्तान की प्लेइंग-6: ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी (कप्तान), इरफान खान, अहमद दानियाल, मुहम्मद शहजाद। क्या है हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट? हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस क्रिकेट जगत का एक बेहद अनोखा और पुराना टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। यह इवेंट मुख्य रूप से हॉन्ग कॉन्ग के क्रिकेटरों और स्थानीय फैंस को दुनिया के टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लाइव खेलते हुए देखने का मौका देने के लिए बनाया गया था। ICC एसोसिएट मेंबर होने के कारण हॉन्ग कॉन्ग के पास तब बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मंच नहीं था।

IIT से कठिन है कोरिया का ये एग्जाम, पास होते ही खुलते हैं शादी और कामयाबी के रास्ते!

कोरिया में सुनुंग प्रवेश परीक्षा के दौरान AI स्मार्ट चश्मों से नकल करने वालों पर सरकार सख्ती करेगी। दोषी छात्रों पर आपराधिक केस दर्ज होगा और परीक्षा देने पर रोक लग सकती है। AI स्मार्ट चश्मों से नकल करने वाले छात्रों पर साउथ कोरिया में आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। दोषी छात्रों पर तीन साल तक कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की रोक लगाने की तैयारी है। हर परीक्षा केंद्र पर संदिग्ध स्मार्ट चश्मों की पहचान के लिए विशेष कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। साउथ कोरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस स्मार्ट चश्मों के जरिए परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ऐसे छात्रों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने और सजा को पहले से ज्यादा सख्त करने की तैयारी कर रही है। नए नियमों के तहत स्मार्ट चश्मों से नकल करते पकड़े जाने वाले छात्रों को तीन साल तक दोबारा कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने से रोका जा सकता है। फिलहाल इस अपराध के लिए एक साल तक परीक्षा देने पर प्रतिबंध का प्रावधान है। साउथ कोरिया के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ली जून-ह्युक ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि मंत्रालय स्मार्ट चश्मों से नकल करने वाले छात्रों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराएगा। हालांकि, ये बदलाव अगले महीने होने वाली प्रवेश परीक्षा में लागू होने की संभावना कम है। अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा में अब केवल



20 दिन बचे हैं और इतने कम समय में नियमों में बदलाव करना व्यावहारिक नहीं है। योजना है कि अगले साल से नए नियम लागू किए जाएं। क्या है साउथ कोरिया की सुनुंग परीक्षा? साउथ कोरिया में कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा को सुनुंग (Suneung) कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी माना जाता है। यहां बेहतर शिक्षा और नौकरी के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से भी इस परीक्षा का खास महत्व है। इस परीक्षा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी के लिसनिंग टेस्ट के दौरान 35 मिनट तक देशभर में उड़ानों पर रोक लगा दी जाती है। बैंकों और सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को भी एक घंटे देरी से काम पर पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में ट्रैफिक की परेशानी न हो। परीक्षा करीब आठ घंटे तक चलती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पेपर में भी भारत के IIT परीक्षा की तरह ही 1 से 2 परसेंट कैंडिडेट ही पास होते हैं। सुनुंग परीक्षा में एक ही दिन में 8 घंटे का लगातार मैराथन एग्जाम होता है। तीन छात्रों के पकड़े जाने के बाद सख्ती स्मार्ट चश्मों से नकल रोकने के लिए सरकार ने यह कदम हाल की घटनाओं के बाद उठाया है। सियोल की एक यूनिवर्सिटी में निबंध परीक्षा के दौरान तीन छात्रों को स्मार्ट चश्मा पहने या अपने पास रखते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा ताइवान की नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी में भी एक छात्र को AI स्मार्ट चश्मे की मदद से नकल करने पर प्रवेश परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्मार्ट चश्मों में कैमरा और AI असिस्टेंट जैसी सुविधाएं होती हैं। इनकी मदद से फोटो-वीडियो लेने के साथ सवालों के जवाब भी हासिल किए जा सकते हैं। नए नियमों के तहत साउथ कोरिया के हर परीक्षा केंद्र पर एक विशेष कर्मचारी तैनात किया जाएगा, जो संदिग्ध स्मार्ट चश्मों की पहचान करेगा।

यूनुस ने रची थी हसीना के तख्तापलट की साजिश! पूर्व सहयोगी ने खोल दी पोल, विदेशी एजेंसी के पत्रकार ने की थी मदद





बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से विदाई को लेकर नया दावा सामने आया है। पूर्व प्रेस सचिव ने AFP पत्रकार पर यूनुस और छात्र नेताओं के बीच संपर्क कराने का आरोप लगाया है। शफीकुल आलम ने हसीना की सत्ता से विदाई से पहले संपर्क का दावा किया उनके मुताबिक AFP पत्रकार कदरुद्दीन शिशिर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई छात्र नेताओं ने 5 अगस्त से दो दिन पहले यूनुस से संपर्क किया था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2024 से भारत में रह रही हैं। अगस्त 2024 में सरकार विरोधी छात्र आंदोलन के बाद हुए तख्तापलट के कारण हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब उनकी सरकार तख्तापलट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। मुहम्मद यूनुस के पूर्व प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने हाल ही में खुलासा किया है कि अगस्त 2024 में हुए आंदोलन साजिश के तहत करवाए गए थे। आलम ने दावा किया कि 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले ही मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने की योजना बन गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि AFP के एक पत्रकार ने छात्र नेताओं और यूनुस के बीच संपर्क स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। AFP पत्रकार ने निभाई थी अहम भूमिका शफीकुल आलम के मुताबिक, 5 अगस्त 2024 को हसीना के सत्ता छोड़ने से दो दिन पहले छात्र नेताओं ने यूनुस से संपर्क किया था। वे चाहते थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालें। फेसबुक पोस्ट में आलम ने AFP की ढाका स्थित फैक्ट-चेक टीम के तत्कालीन संपादक कदरुद्दीन शिशिर का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के बीच शुरुआती बातचीत कराई थी। आलम ने लिखा कि शिशिर ने इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पत्रकार ने तत्कालीन सरकार के दौरान हुई हत्याओं के वीडियो सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे।

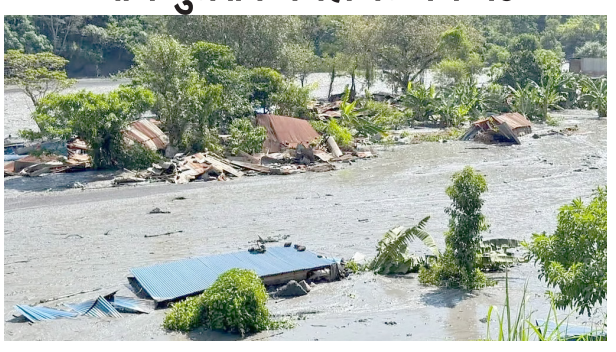
इजरायल में मुसलमान कहां से आए ? ये तो यहूदियों का देश; जानें इतिहास की पूरी कहानी

इजरायल को यहूदियों का देश कहा जाता है, लेकिन यहां करीब 20 प्रतिशत आबादी अरब मूल की है। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। जानिए उनके अधिकारों और राजनीतिक भूमिका की पूरी कहानी। इजरायल की कुल आबादी में करीब 20 प्रतिशत अरब मूल के लोग हैं, जिनमें 80 प्रतिशत मुस्लिम हैं। 1948 में इजरायल बनने के बाद यहां रह गए अरब परिवारों को नागरिकता मिली और वे इजरायली अरब कहलाए। जमीन, गरीबी और कथित भेदभाव के बावजूद अरब पार्टियां इजरायल की राजनीति में अहम भूमिका निभा रही हैं। इजरायल के हालिया आम चुनाव में अरब नेतृत्व वाली पार्टियां किंगमेकर बनकर उभरी हैं। 120 सीटों वाली इजरायली संसद में अरब पार्टियों ने कुल 19 सीटें जीती हैं। ऐसे में सरकार गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को यहूदियों का देश बताने वाले इजरायल में करीब 20 प्रतिशत आबादी अरब मूल के लोगों



की है और इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं? आखिर इजरायल में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे पहुंची और वहां रहने वाले अरब नागरिकों की स्थिति कैसी है? दरअसल, इसकी कहानी 1948 में इजरायल के गठन से जुड़ी है। उस समय इस इलाके में रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी अरब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। हालांकि, बड़ी संख्या में अरब परिवार वहीं रह गए। बाद में इन्हें इजरायल की नागरिकता दे दी गई। आज इन्हें इजरायली अरब कहा जाता है। ये लोग वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी अरबों से अलग हैं। इजरायल की कुल आबादी में अरब मूल के लोगों की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है। इस समुदाय में लगभग 80 प्रतिशत मुस्लिम हैं, जबकि बाकी ईसाई और ड्रूज समुदाय से आते हैं। इनमें से कई लोग खुद को फिलिस्तीनी पहचान से भी जोड़ते हैं। इजरायल में अरब नागरिकों की स्थिति कैसी है? इजरायल खुद को यहूदी और लोकतांत्रिक देश बताता है।

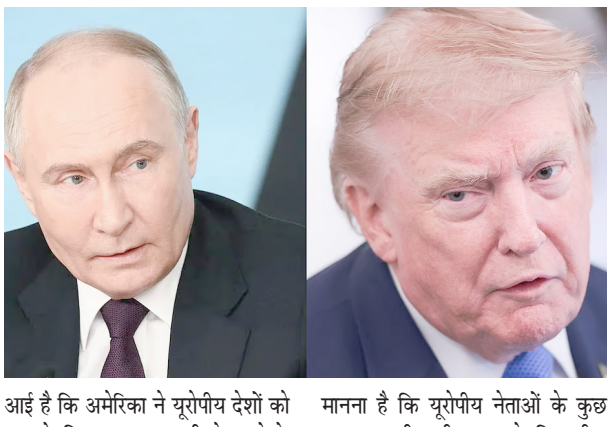
भूटान में ग्लेशियर फटने से भारत में बाढ़ का खतरा, असम-बंगाल में अलर्ट; 10,000+ लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए



भूटान की शिंताफू झील में GLOF के बाद संकोश नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने असम-बंगाल के लिए एडवाइजरी जारी की। oभूटान में ग्लेशियर फटने से असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। GLOF का पूरा नाम 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' है। 6,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। भूटान में शिंताफू झील में गुरुवार को ग्लेशियर फटने के बाद भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। भूटान में अचानक आई बाढ़ की सूचना के बाद, केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने असम और पश्चिम बंगाल के लिए एक विशेष बाढ़ एडवाइजरी जारी की है। इससे धुबरी जिले और अलीपुरद्वार में जल स्तर के अचानक बढ़ने की आशंका को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

पुतिन से डीजल डील होते ही बदले अमेरिका के सुर, पेंटागन ने यूरोपीय देशों को चेताया, कहा- रूस पर बोलने से बचो

रूस को लेकर ट्रंप प्रशासन के रुख में बदलाव के बीच अमेरिका ने यूरोपीय नेताओं को बयानबाजी में संयम बरतने की सलाह दी है। इससे NATO के भीतर मतभेद बढ़ने के संकेत मिले हैं। पेंटागन ने यूरोपीय नेताओं को रूस के खिलाफ बयानबाजी में संयम की सलाह दी एल्ब्रिज कोल्बी ने बाल्टिक देशों के अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाया ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए रूस से बातचीत की कोशिश कर रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक महीने पहले रूस को दुनिया से अलग-थलग करने के लिए रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना बना रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद रूस से एक बड़ी तेल डील कर ली। इसके बाद से ही रूस को लेकर ट्रंप प्रशासन के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। इसी बीच खबर



आई है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के अधिकारियों ने यूरोपीय नेताओं को रूस के खिलाफ उकसावे वाली बयानबाजी करने से बचने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यूरोपीय नेताओं के कुछ बयान महाद्वीप की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं हैं। यूरोपीय सरकारों को सख्त चेतावनी जानकारी के मुताबिक, पेंटागन ने लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया समेत कई यूरोपीय देशों के नेताओं को रूस के खिलाफ कोई भी बयान देते समय संयम बरतने को कहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पेंटागन की ओर से यह हिदायत बाल्टिक देशों के अलावा और किन यूरोपीय सरकारों को दी गई है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी भी यह संदेश देने वाले अमेरिकी अधिकारियों में शामिल थे। कोल्बी यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की समीक्षा से जुड़े अहम अधिकारी हैं। एल्ब्रिज कोल्बी ने यूरोपीय देशों से क्या कहा? जानकारी के मुताबिक, एल्ब्रिज कोल्बी ने बाल्टिक देशों के एक अधिकारी से रूस के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोल्बी ने इस दौरान अधिकारी को उन बयानों का उदाहरण दिया, जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरह फंस चुका है और हताश होकर कदम उठा रहा है। संदेश में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिहाल के बयान का भी जिक्र किया गया है।

31 अक्टूबर यौम-ए-वफात पर विशेष।

स्वतंत्रता सेनानी मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खा़दर

विदेशी शासन से आजादी और सामाजिक सुधार के लिए लड़ने वाले मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खादर का जन्म 28 दिसंबर 1873 में त्रावणकोर रियासत के चिरायिनकिल तालुक के वक्कम गांव में हुआ था, जो तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी का अभिन्न अंग था। उनकी मां आशा बीवी थीं और उनके पिता मोहम्मद कुंजू एक धनी व्यापारी थे। मुहम्मद खादर ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। उन्हें पढ़ाने के लिए कई विद्वान नियुक्त किए गए थे। उन्होंने तेजी से प्रगति करके अपने शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया और अरबी, फारसी, उर्दू, तमिल, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता हासिल की। अपने देश के प्रति प्रेम और प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्होंने 1905 में मलयाली साप्ताहिक समाचार पत्र 'स्वदेशभिमानी' शुरू



किया। यह घोषणा करते हुए कि समाचार पत्र किसी भी रूप में लोगों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करने में संकोच नहीं करेगा, मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खादर ने ब्रिटिश अधिकारियों और रियासत के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और बुरे कामों को उजागर किया। इससे नाराज अधिकारियों ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस को सील कर दिया। उसके बाद मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खादर ने सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया और विदेशी शासकों के बुरे कामों के अलावा समाज में भ्रष्टाचार और तर्कहीन कुप्रथाओं पर किताबें लिखीं। आधुनिक शिक्षा और महिला विकास की आवश्यकता पर लिखने के अलावा उन्होंने उन्हें साकार करने के लिए कुछ गतिविधियाँ कीं। अपने समुदाय के रूढ़िवादी लोगों और अधिकारियों द्वारा उत्पन्न की गई सभी बाधाओं के बावजूद, वे उस मार्ग पर आगे बढ़े, जो उन्हें विश्वास था कि समाज के लिए अच्छा होगा। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि किताबें कितनी प्रभावी होती हैं, उन्होंने 1831 में 'इस्लामिक पब्लिशिंग हाउस' शुरू किया और कई किताबें और पत्र प्रकाशित और लोकप्रिय किए। धीरे-धीरे सरकारों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के महत्व को समझना शुरू किया और उनके सुझावों पर अमल किया। मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खादर, जिन्होंने एक साहित्यिक सिपाही के रूप में, समाज को स्वतंत्रता, प्रगति और आधुनिकता के मार्ग पर अंतिम समय तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की, उनका निधन 31 अक्टूबर, 1932 को हुआ। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत सरकार ने 'स्वदेशभिमानी' का प्रेस खुलवाकर मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खादर के उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1910 में ही सील कर दिया था।

नोट- भारत सरकार ने मौलवी वक्कम मुहम्मद अब्दुल खादर साहब के सम्मान में 2021 में एक डाक टिकट स्मारक जारी किया।

संदर्भः द इम्मोर्टल्स-2 , सैयद नसीर अहमद द्वारा, 9440241727)

संकलन हसरत अली

शेरपुर जिला मुज़फ्फरनगर उत्तर प्रदेश

मिरा-भाईंदर के विकास का

कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए आवंटित निधि के उपयोग, विभिन्न समाज भवनों के उद्घाटन, साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक, क्लस्टर योजना से बाहर रखी गई इमारतों के नक्शों की मंजूरी तथा शहर में नालों के निर्माण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पांडुरंगवाड़ी सिग्नल और बायपास, घोड़बंदर किले के पास पर्यटन विभाग की जमीन हस्तांतरित करने, स्वास्थ्य एवं परिवहन सेवाओं में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को महानगरपालिका की सेवा में शामिल करने तथा भारतरत्न लता मंगेशकर संगीत विद्यालय शुरू करने के विषय भी उठाए गए। मंत्री सरनाईक ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर 15 नवंबर के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अन्य लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पानी माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश शहर के कुछ इलाकों में पानी की कमी और बोरवेल के माध्यम से पानी की कथित अवैध बिक्री को लेकर मंत्री प्रताप सरनाईक ने नाराजगी जताई। उन्होंने महानगरपालिका और पुलिस प्रशासन को संयुक्त कार्रवाई कर अवैध रूप से पानी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी नागरिकों की बुनियादी जरूरत है और इसकी बिक्री के नाम पर आम लोगों का आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन इलाकों में पानी की समस्या है, वहां महानगरपालिका के माध्यम से तत्काल वैकल्पिक बोरवेल व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। दिवाली की छुट्टियों में बच्चों के लिए खुलेगा बाळासाहेब ठाकरे कलादालन हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कलादालन को प्रशासनिक मंजूरी से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया के कारण शुरू करने में आ रही बाधाओं को देखते हुए मंत्री सरनाईक ने विशेष पहल की। उन्होंने महानगरपालिका आयुक्त को निर्देश दिया कि तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने तक दिवाली की छुट्टियों में इस कलादालन को बच्चों के लिए खोला जाए, ताकि शहर के विद्यार्थियों और बच्चों को सांस्कृतिक, कलात्मक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ मिल सके। मंत्री की इस पहल से दिवाली की छुट्टियों में बच्चों को एक नया अनुभव मिलने की उम्मीद है। लंबित विकास कार्यों की होगी समीक्षा मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मिरा-भाईंदर का विकास केवल कागजों और बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक देरी के कारण लंबित परियोजनाओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिवाली की छुट्टियां समाप्त होने के बाद प्रत्येक विभाग के कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट की स्वयं समीक्षा करेंगे। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

लापरवाही बरतने पर कारोबारी ही

सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से FDA ने पूरे राज्य में अपने अभियानों और प्रयासों को काफी तेज कर दिया है। एफडीए के प्रमुख तुकाराम मुंढे ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने एक प्रमुख प्रणालीगत पहल के तहत विभिन्न खाद्य क्षेत्रों के लिए लगभग 15 कंप्लायंस ऑर्डर जारी किए हैं। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs), आम नागरिकों और एफडीए के अधिकारियों के बीच नियमों को लेकर पूरी स्पष्टता, सरलता और व्यापक जागरूकता लाना है। नियमों में पारदर्शिता और सरलता लाने पर जोर तुकाराम मुंढे के अनुसार, राज्य भर में जारी किए गए इन अनुपालन आदेशों का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी घटकों को यह भली-भांति समझ में आए कि उन पर कौन से नियम और कानून लागू होते हैं तथा उन्हें किस प्रकार का संचालन करना अनिवार्य है। अक्सर देखा जाता है कि स्पष्टता के अभाव में नियमों का उल्लंघन होता है। ऐसे में इन विशेष आदेशों के जरिए एफडीए ने प्रत्येक खाद्य क्षेत्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि कोई भी कारोबारी अनजाने में नियमों का उल्लंघन न करे। कारोबारियों के साथ अधिकारियों की भी जवाबदेही एफडीए प्रमुख तुकाराम मुंढे के इस बयान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल व्यवसायियों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर भी समान रूप से जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि खाद्य व्यवसाय संचालक तय मानकों व नियमों का पालन करने में फेल होते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त परिणाम और दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही, यदि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अपने अधिकारी राज्य में इन नियमों को लागू करने या उनका एनफोर्समेंट करने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रशासनिक परिणाम और कार्रवाई तय की जाएगी। नागरिकों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा को मजबूती तुकाराम मुंढे ने इस बात पर विशेष बल दिया कि खाद्य सुरक्षा तंत्र में आम नागरिकों को जागरूक बनाना बेहद जरूरी है। इन अनुपालन आदेशों के माध्यम से आम जनता को भी यह जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता के लिए कौन से मानक निर्धारित हैं। जब नागरिक जागरूक होंगे और अधिकारियों व कारोबारियों को अपने कर्तव्यों का स्पष्ट ज्ञान होगा, तब पूरे महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा का एक मजबूत और भरोसेमंद माहौल तैयार हो सकेगा।

SIR की समय-सीमा बढ़ी,

मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी अंतिम तारीख 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी है। इसके साथ ही दावों और आपत्तियों के निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख में भी बदलाव किया गया है। अब महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी होगी। छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बदला कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र समेत दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड के SIR कार्यक्रम में संशोधन किया। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की ओर से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद आयोग ने सभी को अलग-अलग पत्र भेजकर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। महाराष्ट्र में अब 13 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे दावे महाराष्ट्र में पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 13 नवंबर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मतदाताओं को अपनी जानकारी में सुधार कराने या मतदाता सूची से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। 25 नवंबर तक होगा दावों और आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, महाराष्ट्र में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण अब 25 नवंबर तक किया जाएगा। इससे पहले इसके लिए 10 नवंबर की समय सीमा निर्धारित थी। आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। 30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची महाराष्ट्र में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 30 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार इसकी तारीख अलग निर्धारित थी। गौरतलब है कि राज्य में SIR की मसौदा मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद मतदाताओं को सूची में नाम, पते और अन्य विवरणों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। दिल्ली में भी बढ़ाई गई समय सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ दिल्ली में भी SIR कार्यक्रम की तारीखें बदली गई हैं। यहां दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। वहीं, दावों के निस्तारण की समय सीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

मुंबई में कचरा फेंकते ही AI कैमरा

को साफ-सुथरा रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। एमसी अधिकारियों की पहल पर शुरू हुआ प्रयोग बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देश पर अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन में यह पहल शुरू की गई है। ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के उपायुक्त किरण दिघावकर के नेतृत्व में तथा उपायुक्त प्रशांत सपकाले और जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई की पहल पर इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। बीएमसी इस प्रयोग के परिणामों की समीक्षा करेगी। यदि यह सफल रहता है, तो मुंबई के दूसरे कचरा संवेदनशील स्थानों पर भी ऐसे एआई कैमरे लगाए जा सकते हैं।

पृष्ठ 1/8 का शेष

50 प्रतिशत वाहनों पर नहीं लगे

मिश्रधातु से बनाई जाती है। इसमें INDIA लिखी रिफ्लेक्टिव फिल्म, क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम, नीले रंग में IND अक्षर और लेजर से अंकित 10 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर होता है। इसकी खास बनावट के कारण प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है। वाहन की पहचान और सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। केदारों की जवाबदेही हो तय HSRP लगाने में देरी को लेकर RTO प्रमुखों को नोटिस जारी होने के बाद कुछ अधिकारियों ने अलग सवाल उठाए हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि देरी के लिए केवल परिवहन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। HSRP लगाने का वास्तविक काम अधिकृत ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग, अपॉइंटमेंट, प्लेट की उपलब्धता, केंद्रों की संख्या और सेवा क्षमता की भी जांच जरूरी है। परिवहन विभाग ने वायुवेग टीमों के जरिए कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान भी चलाए हैं। ऐसे में अधिकारियों के साथ ठेकेदारों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

बुलेट ट्रेन को मिलेगी 14

भूमिका निभाएंगे। क्या है टीएसएस? ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) हाई-स्पीड रेल की विद्युत आपूर्ति प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये ग्रिड से बिजली प्राप्त कर उसे आवश्यक वोल्टेज स्तर पर परिवर्तित करते हैं और ट्रैक्शन पावर सिस्टम को आपूर्ति करते हैं, जिससे बुलेट ट्रेन का संचालन संभव होता है। कहां हो रहे स्थापित महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर और ठाणे डिपो में ट्रैक्शन सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं। वहीं गुजरात में वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, महेमदावाद, अहमदाबाद और साबरमती डिपो में इनकी स्थापना की जा रही है। बि 2×25 केवी तकनीक से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन गुजरात के ट्रैक्शन सबस्टेशनों को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 220 केवी अंबेथा ग्रिड सबस्टेशन से बिजली मिलेगी। इसके बाद आधुनिक 2×25 केवी ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम के जरिए वायाडक्ट पर लगे ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) तक बिजली पहुंचाई जाएगी। ट्रैक्शन पावर सप्लाई नेटवर्क की सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर से लगातार रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। 14 ट्रैक्शन सबस्टेशनों का यह नेटवर्क देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। लिमोरा में पहला सबस्टेशन अंतिम चरण में गुजरात के नवसारी जिले के बिलिमोरा में पहला ट्रैक्शन सबस्टेशन निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 18 हजा र वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस परिसर में विद्युत पारेषण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। कंट्रोल पैनल, चेंजओवर स्विच, ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर भवन में उपकरणों की स्थापना पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सभी गैन्ट्री टावर और बीम लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। फिलहाल उपकरणों के परीक्षण और कमीशनिंग की प्रक्रिया जारी है।

पेड़ों की कटाई पर

कटाई हो रही है। उन्होंने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की घोषणाएं खोखली साबित हो रही हैं। 'महाराष्ट्र के हित में नहीं है परियोजना' सपकाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण का संकल्प लिया है, जबकि महाराष्ट्र में पेड़ों की कटाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने कर्जत के जंगलों में पौधारोपण कर प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। सपकाल के मुताबिक, कमीशन के लालच में पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी पेड़ों की कटाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्जत-भीमाशंकर के जंगलों में बन रही यह परियोजना महाराष्ट्र के हित में नहीं है। 33 करोड़ पेड़ लगाने के संकल्प पर भी उठाए सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार के पुराने वृक्षारोपण अभियान का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने 33 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। उन्होंने पूछा कि उस अभियान के तहत लगाए गए पेड़ अब कहां हैं और उनका क्या हुआ। हर्षवर्धन सपकाल ने चेतावनी दी कि राज्य के लोग महाराष्ट्र के हितों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि, पेड़ों की कटाई और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर उनके ये आरोप हैं।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव

की पार्टी ने दोनों सीटें जीतीं राकां (शरद गुट) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। पुणे से हर्षदा देशमुख-जाधव और छत्रपति संभाजीनगर से प्रतापसिंह पाटिल ने जीत दर्ज की। पार्टी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दर्ज किया। कांग्रेस और शिंदे सेना का 50 प्रतिशत स्ट्राइक रेट कांग्रेस ने नागपुर स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। नागपुर में अभिजीत वंजारी ने जीत हासिल की, जबकि अमरावती में कांग्रेस की अदिति पोहरे को हार मिली कांग्रेस ने दो में से एक सीट जीतकर 50 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दर्ज किया। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) ने पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे थे। अमरावती में किरण सरनाईक ने जीत दर्ज की, जबकि पुणे शिक्षक सीट पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवार सचिन सानप को पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट भी 50 प्रतिशत रहा। पढ़े-लिखे मतदाताओं ने भाजपा को नकारा महाराष्ट्र विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटों के चुनाव परिणामों को लेकर सियासत गरमा गई है। एमवीए की तीन सीटों पर जीत और सत्तारूढ़ महायुति को दो सीटें मिलने के बाद शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राऊत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि राज्य के स्नातक मतदाताओं ने भाजपा और उसके सहयोगियों को नकार दिया है। राऊत ने तंज कसते हुए कहा कि पढ़े-लिखे मतदाताओं ने भाजपा को उसकी जगह दिखा दी। महाराष्ट्र में भाजपा की हार का कारण चुनाव मतपत्रों के जरिए कराया जाना है। राऊत ने हालांकि यह भी माना कि चुनाव में सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों खेमों में गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन नहीं हुआ।

विरार-अलिबाग कॉरिडोर से प्रभावित किसानों को मिले उचित मुआवजा : सांसद बाल्या मामा

कॉरिडोर के लिए नई दर निर्धारण समिति बनाने और बिजली लाइनों के नीचे आने वाली जमीनों का भी मुआवजा देने की मांग

सांसद सुप्रिया सुले के साथ युवा नेता सुमित म्हात्रे ने की राजस्व मंत्री से मुलाकात

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर और भिवंडी तालुका में प्रस्तावित अति उच्चदाब बिजली पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से की है। इस संबंध में गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) के युवा नेता सुमित म्हात्रे ने सांसद सुप्रिया सुले और प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राजस्व मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बैठक में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के किसानों की जमीन अधिग्रहण के दौरान उचित मुआवजा, समान दर निर्धारण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास सहित विभिन्न मुद्दे उठाए गए।विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के लिए बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। सांसद बाल्या मामा ने मुआवजा तय करने के लिए



अलग से नई दर निर्धारण समिति गठित करने और उसमें प्रभावित किसानों अथवा उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की। साथ ही अधिग्रहित जमीनों के लिए समान रूप से दो का गुणांक लागू कर गांववार न्यायसंगत दरें निर्धारित करने तथा किसानों का उचित मुआवजा देकर पुनर्वास करने की मांग भी की गई। खावड़ा-4सी पावर ट्रांसमिशन परियोजना के तहत भिवंडी तालुका के 20 गांवों से अति उच्चदाब बिजली की लाइनें गुजरने वाली हैं। इससे किसानों की जमीन प्रभावित होगी और बिजली लाइनों के नीचे आने वाली जमीनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगेगा। सांसद बाल्या मामा ने मांग की कि किसानों को केवल बिजली के टावरों के लिए अधिग्रहित जमीन का ही नहीं, बल्कि बिजली लाइनों के नीचे प्रभावित होने वाली जमीन का भी उचित मुआवजा दिया जाए। युवा नेता सुमित म्हात्रे ने बताया कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इन मांगों पर चर्चा के लिए विशेष बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर प्रभावित किसानों को उचित न्याय दिलाने के लिए सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया गया है।

बुलेट ट्रेन को मिलेगी 14 ट्रैक्शन सबस्टेशनों से बिजली! महाराष्ट्र और गुजरात में बन रहे पावर स्टेशन



मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 14 ट्रैक्शन सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 और गुजरात में 9 सबस्टेशन स्थापित होंगे। बिलिमोरा में पहला सबस्टेशन अंतिम चरण में, 2×25 केवी तकनीक से मिलेगी बिजली। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली देश की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की रफ्तार न थमे इसके लिए बिजली आपूर्ति का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। 508 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कुल 14 ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें 5 महाराष्ट्र और 9 गुजरात में होंगे। ये अत्याधुनिक सबस्टेशन बुलेट ट्रेन के संचालन में महत्वपूर्ण ...शेष 7 पर

50 प्रतिशत वाहनों पर नहीं लगे HSRP! महाराष्ट्र के 27 RTO प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस

महाराष्ट्र में पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की धीमी रफ्तार पर सरकार सख्त। परिवहन आयुक्त ने लक्ष्य पूरा न करने पर राज्यभर के 27 RTO प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। HSRP लगाने में देरी पर परिवहन आयुक्त ने 27 RTO प्रमुखों को नोटिस दिया। अधिकारियों को 7 दिनों में जवाब देने का निर्देश, कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ठेकेदारों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही की जांच की मांग उठी। महाराष्ट्र में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की धीमी रफ्तार अब परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भारी पड़ने वाली है। पता चला है,समय सीमा बीत जाने के बाद भी निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले आधे से कम वाहनों पर ही HSRP लगाने



से राज्य परिवहन विभाग को सरकार ने फटकार लगाई है। इस मामले में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर ने राज्यभर के 27 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 7 दिन में देना होगा जवाब परिवहन अधिकारियों को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 50 प्रतिशत से अधिक वाहनों पर अब तक HSRP नहीं लगाई जा सकी है। इस सुस्ती को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त ने संबंधित RTO प्रमुखों से पूछा है कि बार-बार समीक्षा और निर्देशों के बावजूद प्लेट लगाने के काम में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हुई? उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त जुलाई से अब तक इस अभियान की तीन बार समीक्षा कर चुके हैं। 7 अक्टूबर को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी इस संबंध में समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सामने आया कि करीब 25 से 30 RTO कार्यालयों में 50 प्रतिशत से भी कम वाहनों पर HSRP लगाई गई है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए थे। ठे सुरक्षा के लिहाज से क्यों जरूरी है HSRP HSRP प्लेट विशेष एल्यूमीनियम ...शेष 7 पर

मुंबई में कचरा फेंकते ही AI कैमरा देगा चेतावनी, BMC ने माहिम में शुरू किया अनोखा प्रयोग

मुंबई में खुले में कचरा फेंकने वालों को रोकने के लिए बीएमसी ने माहिम में एआई कैमरा और लाउडस्पीकर सिस्टम लगाया है। कचरा फेंकते ही लाउडस्पीकर पर स्वच्छता का संदेश बजेगा। BMC ने माहिम में कचरा रोकने के लिए AI कैमरे का पायलट शुरू किया। कचरा फेंकते ही लाउडस्पीकर से स्वच्छता संदेश सुनाई देगा। प्रयोग सफल रहा तो मुंबई के अन्य इलाकों में भी AI कैमरे लगाए जाएंगे। मुंबई शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और बार-बार गंदगी जमा होने की समस्या से निपटने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा लिया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने के इरादे से पहुंचता है, तो वहां लगा एआई कैमरा उसकी गतिविधि



पहचानकर लाउडस्पीकर के जरिए स्वच्छता का संदेश प्रसारित करेगा। बीएमसी ने इस तकनीक का प्रायोगिक इस्तेमाल माहिम स्थित गजानन वाटिका परिसर में शुरू किया है। कैसे काम करेगा AI कैमरा? मुंबई शहर में ऐसे कई स्थान हैं, जहां बार-बार कचरा जमा होने से गंदगी फैलती है। बीएमसी इन्हें गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स (GVP) यानी कचरा जमा होने की आशंका वाले स्थानों के रूप में चिह्नित कर रही है। इन जगहों पर निगरानी बढ़ाने के साथ लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। माहिम के गजानन वाटिका परिसर में लगाए गए एआई कैमरे को लाउडस्पीकर से जोड़ा गया है। जब कोई व्यक्ति कचरा फेंकने के लिए वहां पहुंचता है, तो कैमरा उसकी गतिविधि पहचानता है। इसके तुरंत बाद लाउडस्पीकर से परिसर को साफ रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाती है। बी नागरिकों के सहयोग से ही सफल होगी पहल मुंबई बीएमसी को उम्मीद है कि मौके पर ही लाउडस्पीकर से मिलने वाला संदेश लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से रोकेगा। इस पहल का उद्देश्य केवल निगरानी करना नहीं, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। मनपा ने लोगों से सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक परिसरों में कचरा नहीं फेंकने की अपील की है। प्रशासन का मानना है कि तकनीक के साथ नागरिकों का सहयोग मिलने पर शहर...शेष 7 पर

मुंबई के गरीब नगर में रेलवे ने 94 ढांचों पर चलाया बुलडोजर, बांद्रा टर्मिनस का होगा विस्तार



मुंबई के गरीब नगर में वेस्टर्न रेलवे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर 94 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन के खाली होने से बांद्रा टर्मिनस का कायाकल्प होगा। गरीब नगर में वेस्टर्न रेलवे ने 94 संरचनाओं को ध्वस्त किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बांद्रा टर्मिनस पर नया प्लेटफॉर्म (PF-8) बनेगा। ट्रेनों के लिए स्टेबलिंग फैसिलिटीज विकसित होंगी। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे ने बांद्रा (पूर्व) स्थित गरीब नगर इलाके में बुनियादी ढांचे के विस्तार के रास्ते में आ रहे शेष 94 अवैध और अस्थाई निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी है। इससे पहले मई महीने में भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। हालांकि, उस समय पात्र लोगों के सुचारु पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन 94 संरचनाओं को छोड़ दिया गया था।

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486